Conversion of Miraj Bangalore Railway Line

1476. SHRI H.HANUMANTHAPPA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the number of pending proposals for the conversion of metre gauge rail lines into broad gauge;

(b) what are the norms for taking up such projects;

(c) whether any proposal for conversion of Miraj Bangalore rail line is ending;

(d) what is the approximate cost involved; and

e) by when the conversion work is y to start?

IE MINISTER OF STATE OF THE ISTRY OF RAILWAYS (SHRI)HAVRAO SCINDIA): (a) There ; on-going projects for conversion of e Gauge line to Broad Gauge and more has been proposed during 1989-

) Following norms are generally pted for taking up gauge conversion jects:

i)When it is found that the traffic likely to develop in future cannot be handled on the existing system,

(ii)When the magnitude of transhipment involved is such that it is uneconomical or not feasible to handle the anticipated volume of traffic, and

(iii)When it is needed for providing speedy and uninterrupted means of communication to areas having potential for growth.

(c) to (e) A survey was carried out for conversion of Miraj-Bangalore and other connected branch lines totalling 1934 km from MG to BG The estimated cost of conversion was approximately Rs. 500 crores at 1984 price level. On account of acute constraint of resources and unremunerativeness of the project, the same could not be considered. The survey is now proposed to be updated to work out the latest cost and traffic prospects.

इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में घोटाले का समाचार

1477. **श्री अश्विनी कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद में वस्तुओं के क्रय-विक्रय के नाम पर लाखों रुपये के घोटाले के संबंध में 1 जनवरी, 1989 की "मायो" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि लाखों रुपये मूल्य के उपकरण खरीदे तो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये उपकरण कहां चले जाते हैं, इसका पता नहीं लगता;

(ख) क्या उक्त संस्था को इस प्रकार के आरोपों-प्रत्यारोपों से अलग रखने के लिये केन्द्रीय स्तर पर कोई कार्यवाही की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संस्थान के कार्यकरण को चुस्त बनाने और वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और इन उपायों का क्या परिणाम निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल.पी.साही): (क)से (ग) भारतीय खनन स्कूल, धनबाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था है। वित्त समिति तथा कार्यकारी बोर्ड में, अन्य बातों के साथ साथ, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि है। संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्कूल के लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक तौर पर की जाती है तथा वस्तु और उपकरणों की सभी खरीद संस्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से स्कूल की उपयुक्त समितियों द्वारा की जाती है। स्कूल ने सूचित किया है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अभी तक की गई खरीदारियों में किसी प्रकार की अनियमितताओं